



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 23 मार्च, 1998/ 2 चैत्र, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-9, 31 जनवरी, 1998

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) सिगा/ऊना-1119-33.—यह कि श्रीमती रामप्यारी, प्रधान, ग्राम पंचायत सिगा को इस कार्यालय के समसंख्यित आदेश दिनांक 27 अगस्त, 1997 को राशि के दुहमयों, छलहरण/अनियमितताओं के आरोपों में संलिप्तता पाये जाने के कारण निलम्बित कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा दिनांक 26 नवम्बर, 1997 को उनका उत्तर आंकने उपरांत पद से निलम्बित किया गया।

यह कि श्रीमती रामप्यारी, प्रधान (निलम्बित) द्वारा अपने निलम्बित आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर निर्णय देते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7-1-98 को याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किए हैं कि मामले में नियमित जांच उन द्वारा पारित आदेशों से चार माह के भीतर-भीतर पूर्ण करवाई जाए।

यह कि श्रीमती रामप्यारी, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत सिगा, विकास खण्ड ऊना निम्न राशियों के छलहरण/दुरुपयोग व अनियमितताओं जैसे आरोपों में संलिप्त लगती हैं:—

- (1) मु० 17,029 रु० की राशि का रोकड़ बही में दर्ज न होना तथा पंचायत की बिना पूर्व स्वीकृति से राशि का व्यय किये जाने वाले पंचायत द्वारा यह राशि विभिन्न मद की रसीदों के प्रति एकत्रित की गई है। जिसका व्यय तुरन्त रोकड़ बही पर दर्ज नहीं किया गया तथा तत्पश्चात वित्त नियमों के अन्तर्गत इस राशि के उपयोग के लिए वार्षिक बजट में प्रावधान कर पंचायत की पूर्व स्वीकृति से व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि प्रधान द्वारा इन दोनों मामलों में अनियमितता कर स्वेच्छा से इस राशि का दुरुपयोग किया गया है।
- (2) मु० 10 रु० की राशि रसीद संख्या 000081 के प्रति रूप सहित रिकार्ड में न रखे जाने वाले। प्रधान द्वारा मु० 10 रु० गृहकर की वसूली कर राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं दिया गया और इस आरोप के बचाव की कार्यवाही के लिए प्रधान द्वारा रसीद बुक से रसीद संख्या 000081 को प्रारूप सहित समाप्त किया गया पाया है। वास्तव में यह रिकार्ड ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी की संरक्षणता में उसी द्वारा रसीद काटकर रोकड़ बही पर इन्द्राज की पुष्टि प्रधान द्वारा प्रतिदिन की जानी अपेक्षित थी।
- (3) रसीद संख्या 3 तथा 83 से 93 के प्रतिरूप तथा अन्य रसीदों के प्रति राशि की प्राप्ति का ब्योरा न होने वाले रसीदों के प्रतिरूप का गुम होना तथा राशियों के आय की वास्तविकता पर पर्दा डालने की चेष्टा वास्तव में गम्भीर आरोप है। प्रधान द्वारा इस विषय में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया क्योंकि वह इस बारे में अन्वेषण काल में भी अन्वेषण अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पायी।
- (4) मु० 750 रु० का सीमेंट क्रय करने तथा इसके उपयोग वाले रिकार्ड में इन्द्राज न करने वाले। प्रधान 5 बोरी सीमेंट के उपयोग के प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रही और न ही इन्होंने इसका इन्द्राज स्टोक रजिस्टर पर करवाया। स्पष्ट है कि यह व्यय उन द्वारा अनुचित रूप से दर्शाया गया है।
- (5) मु० 10 रु० गृहकर निर्धारित करने वाले। प्रधान द्वारा स्वेच्छा से मु० 10 रु० नियमों का उल्लंघन कर तथा पंचायत की गैर स्वीकृति से गृहकर निर्धारण कर अपने पद का दुरुपयोग किया है।
- (6) दिनांक 24-9-96 से 17-2-97 तक बैंक से निकाली गई राशि अल्प कोरम द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार निकाले जाने वाले। प्रधान द्वारा इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और इस प्रकार से निकाली गई राशियों को दुरुपयोग की भावना से निकाला जाना संभावित है।
- (7) 5 पेड़ कीकर अवैध रूप से काटकर निलामी करने तथा रिकार्ड में इस बारे कोई भी उल्लेख न करके राशि के अपहरण करने वाले। प्रधान द्वारा कीकर के 5 पेड़ कटवाने से पूर्व कोई भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में न लाई गई और न ही कटान के उपरान्त नियमानुसार निलामी की कार्यवाही की गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रधान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर राशि के छलहरण किया गया प्रतीत होता है।
- (8) मु० 360 रु० बाबत प्लॉट की कच्ची रसीद देकर राशि का छलहरण करने वाले प्रधान द्वारा, यदि मु० 360 रु० की रसीद किसी कारण मोकामे पर दी गई थी तो उसका इन्द्राज तुरन्त रोकड़ बही में पक्की रसीद काट कर दिया जाने अपेक्षित था। अतः प्रधान द्वारा राशि का दुरुपयोग किया गया है।

(9) मु० 829 रु० की मानदेय की स्वीकृत राशि के बजाये मु० 1500 रु० अनुचित रूप से प्राप्त किये जाने बारे। प्रधान द्वारा पंचायत निधि से 829 रु० के स्थान पर 1500 रु० का उपयोग निजी हितों के लिए दुरुपयोग किया गया पाया गया है।

(10) मु० 6085 रु० की पेशगी रिकार्ड संधारित न किये जाने बारे प्रधान द्वारा यह राशि लम्बी अवधि से बतौर पेशगी अपने पास रखी जिसके उपयोग एवं व्यय सम्बन्धी कोई भी रिकार्ड प्रस्तुत न कर राशि का दुरुपयोग किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आरोपों में मामले की वास्तविकता जानने व पूर्ण तथ्य/स्थिति सामने लाने के लिए सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत जांच करवाने का जनहित में निर्णय लिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जोकि उन्हें पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुए श्रीमती रामप्यारी, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत सिगा विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित आरोपों की वास्तविकता जानने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना जिला ऊना को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं तथा साथ ही पंचायत निरीक्षक ऊना को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो कि जांच अधिकारी को जांच के दौरान वांछित रिकार्ड प्रस्तुत करने के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी रखेंगे। इसके साथ-साथ श्रीमती रामप्यारी, प्रधान (निलम्बित) को यह भी आदेश दिये जाते हैं कि वह जांच अधिकारी के सम्मुख जांच के दौरान मौका पर अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करेगी कि क्यों न उन्हें उपरोक्त वर्णित तथ्यों के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (ख) के अन्तर्गत उनके पद से पदच्युत किया जाए।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
आयुक्त एवं सचिव।

### अधिसूचना

शिमला-9, 17 मार्च, 1998

संख्या पी० सी० एच० एच० ए० (4) 13/92-2352-61.—मैं, के० जे० बी० वी० सुब्रह्मण्यम्, निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) निगम, 1997 के नियम 135 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, निम्न अनुसूची में वर्णित पंचायत पदाधिकारियों द्वारा अपन पदों से दिये गए त्याग-पत्रों को तुरन्त स्वीकृत करता हूँ:—

क्रम सं०	जिला का नाम	पंचायत पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	त्याग-पत्र देने का कारण
1.	हमीरपुर	श्रीमती उर्मिला ठाकुर	सदस्य, जिला परिषद् वार्ड बगेहरा।	विधान सभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण।
2.	मण्डी	श्री डी० डी० ठाकुर	अध्यक्ष, जिला परिषद् मण्डी।	व्यक्तिगत

के० जे० बी० वी० सुब्रह्मण्यम्,  
निदेशक।

## खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

## कार्यालय आदेश

शिमला-1, 10 मार्च, 1998

संख्या 1966-2007.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एक0 डी0 एस0 एस0 एम0 एल0-7-39/95-1-765-810, दिनांक 20-1-98 की निरन्तरता में तथा हि0 प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1)(ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनीषा श्रीधर, जिला दण्डाधिकारी, शिमला, जिला शिमला आदेश जारी करती हूँ कि उपरोक्त अधिसूचना आगामी दो महीनों के लिए लागू रहेगी।

मनीषा श्रीधर,  
जिला दण्डाधिकारी, शिमला,  
जिला शिमला (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

## कार्यालय आदेश

सोलन, 9 मार्च, 1998

संख्या सोलन-3-92 (पंच) 3643-48.—विकास खण्ड अधिकारी धर्मपुर ने अपने पत्र संख्या डी0 बी0 डी0 (पंच) 98-5476 दिनांक 21-2-98 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि श्रीमती रोशनी देवी, ग्राम पंचायत बरोटीवाला, वार्ड नं0 3 पंच का देहान्त 5-10-97 को हो जाने के कारण रिक्त हो गया है।

अतः मैं, बी0 एस0 नेन्टा, उपायुक्त, सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(4) के अधीन प्राप्त हैं का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत बरोटीवाला में पंच का पद रिक्त घोषित करता हूँ।

बी0 एस0 नेन्टा,  
उपायुक्त, सोलन।

## विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) अनुभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 19 मार्च, 1998

संख्या एल0 एल0 आर0-ई0(9)-27/95-लेज.—सर्वश्री राम किशोर द्विवेदी, नरेन्द्र मोहन शर्मा और धर्म सिंह अधिवक्ताओं ने उप-मण्डल ऊना, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी एक्ट, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है,

और इस सम्बन्ध में अधिनियम और, नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली हैं,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला मैजिस्ट्रेट, ऊना की सिफारिशों पर, जो कि इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी है, और नोटरी नियम, 1956 के नियम 8 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री राम किशोर द्विवेदी, नरेन्द्र मोहन शर्मा और धर्म सिंह, अधिवक्ताओं को उपमण्डल, ऊना, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर तुरन्त से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निर्देश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,  
सचिव (विधि)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-27/95-Leg. dated 19-3-1998 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## LAW DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 19th March, 1998*

**No. LLR-E(9)-27/95-Leg.**—Whereas S/Shri Ram Kishore Duvedi, Narinder Mohan Sharma and Dharam Singh Advocates, Una have applied for appointment as Notaries under Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial of Sub-Division Una of Una District ;

AND WHEREAS all the formalities required under the said Act and Rules have been completed ;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the District Magistrate, Una who is the competent authority and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the Notaries Rules, 1956 is pleased to appoint S/Shri Ram Kishore Duvedi, Narinder Mohan Sharma and Dharam Singh, Advocates at Una as Notaries within the limits of Una Sub-Division of Una District, Himachal Pradesh, with immediate effect and with the direction that their names may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

Sd/-  
Secretary (Law).

